सरकारी वित्त 2023-24: एक अर्धवार्षिक समीक्षा

हर्षिता यादव, कोवूरी आकाश यादव, रचित सोलंकी, सक्षम सूद, अनूप के सुरेश, समीर रंजन बेहरा और अत्रि मुखर्जी^ द्वारा

वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के दौरान केंद्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति लचीली रही। उनकी प्राप्तियाँ मोटे तौर पर बजट अनुमानों के अनुरूप थीं और पूंजीगत व्यय को संरक्षित करते हुए राजस्व व्यय पर नियंत्रण ने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं और राजकोषीय समेकन के लिए अच्छा संकेत है।

I. परिचय

केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा ऐसे समय में की गई थी जब भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों द्वारा समर्थित उच्च विकास के मामले में 'उज्ज्वल स्थान' के रूप में देखा जा रहा था। केंद्रीय बजट 2023-24 में नागरिकों के अवसरों को बढ़ाने, विकास में तेजी लाने, रोजगार सृजन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड स्तर के पूंजीगत व्यय के आवंटन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना जोर जारी रखा। इसी तरह, राज्यों के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना के लिए आवंटन, 2021-22 में शुरू किया गया, 30 प्रतिशत बढ़ाया गया और 2023-24 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी व्यय की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देते हुए अपने राजस्व व्यय में कटौती की है।

केंद्र ने 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के मध्यम अवधि के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) लक्ष्य के अनुरूप, 2023-24 के लिए राजकोषीय समेकन के एक व्यवहार्य आदेश का लक्ष्य रखा। राज्यों ने भी 2023-24 में राजकोषीय समेकन के लिए प्रयास किया है, सकल घरेलू उत्पाद के 3.1 प्रतिशत के समेकित जीएफडी का बजट रखा है, जो 2022-23 (आरई) में 3.4 प्रतिशत से कम है।[1, 2] केंद्र और राज्यों के लिए सरकारी वित्त, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 (अर्थात्, एच1:2023-24) की अर्धवार्षिक समीक्षा से स्पष्ट है, मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के साथ-साथ मजबूत था। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की संभावना बढ़ गई है।

केंद्र के प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हेड्स जैसे आयकर, निगम कर और माल और सेवा कर (जीएसटी) ने एच 1: 2023-24 में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। व्यय पक्ष पर, केंद्र ने अपने पूंजीगत व्यय का फ्रंट-लोडिंग सुनिश्चित किया है जो महामारी द्वारा पीछे छोड़े गए निशान से आर्थिक सुधार को उत्प्रेरित करेगा। दूसरी ओर, केंद्र ने एच 1: 2023-24 में 2023-24 के लिए अपने राजस्व व्यय को बजट अनुमान के 50 प्रतिशत से नीचे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। राज्यों का कर राजस्व एच 1:2023-24 के दौरान उनके स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ उत्साहजनक रहा। इसके अतिरिक्त, उन्हें हस्तांतरण सूत्र के तहत कर राजस्व (अर्थात राज्यों को समनुदेशन) के हस्तांतरण में 20 प्रतिशत से अधिक की पर्याप्त वृद्धि से लाभ हुआ है। राज्यों ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए केंद्र सरकार की योजना के पीछे एच 1:2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अपने कुल व्यय की गति को भी बनाए रखा है.[3]

^ लेखक भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

1 डेटा 25 राज्यों से संबंधित है जिसके लिए अप्रैल-सितंबर 2023 के डेटा उपलब्ध हैं। जीएफडी-जीडीपी अनुपात का अनुमान उन्हीं 25 राज्यों के लिए जीएसडीपी डेटा का उपयोग करके लगाया जाता है।

2 केंद्र के साथ-साथ राज्यों की अर्धवार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय स्थिति पर विस्तृत विवरण परिशिष्ट तालिका (I से IV) में दिए गए हैं ।

3 अक्टूबर 2023 के अंत तक, केंद्र सरकार ने ₹96,206 करोड़ (पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 2023-24 के बजट के ₹1.3 लाख करोड़ का 74 प्रतिशत) के व्यय को मंजूरी दे दी थी। जिसमें से ₹58,494 करोड़ पहले ही राज्यों को वितरित किए जा चुके हैं।

लेख का शेष भाग इस प्रकार संरचित है: खंड II एच1:2023-24 के लिए केंद्र और राज्यों की (त्रैमासिक आवृत्ति पर) प्राप्ति और व्यय का विश्लेषण करता है। खंड III प्रमुख घाटे के संकेतकों और केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित है। खंड IV 2023-24 की दूसरी छमाही (एच2) के अनुमानों के साथ-साथ 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य) के वित्त पर अनुमान प्रस्तुत करता है । खंड V समापन टिप्पणियों और निकट अवधि के राजकोषीय दृष्टिकोण को निर्धारित करता है।

II. वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में राजकोषीय परिणाम

एच 1:2021-22 और एच 1:2022-23 के दौरान देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप, केंद्र सरकार की बजटीय कुल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक एच 1:2023-24 के दौरान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, पिछले तीन वर्षों के दौरान देखे गए पैटर्न के अनुरूप, केंद्र का कुल व्यय एच 1:2023-24 में बीई के 50 प्रतिशत से नीचे रहा। राज्यों के लिए, प्राप्तियों और व्यय दोनों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, राज्यों का जीएफ़डी एच 1:2023-24 में बीई का 39.8 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जिसका कारण कुल प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि है। फिर भी, राज्यों की कुल प्राप्तियाँ लचीली बनी रहीं, एच 1:2023-24 में बजटीय प्राप्तियों का अनुपात (39.7 प्रतिशत) एच 1:2022-23 (41.2 प्रतिशत) के करीब रहा। व्यय पक्ष पर, राज्यों ने एच 1:2023-24 के दौरान अपने बजटीय कुल व्यय का 39.7 प्रतिशत खर्च किया है, जो मोटे तौर पर पिछले खर्च पैटर्न (चार्ट 1 ए और बी) के अनुरूप है।

ए. प्राप्तियां

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 2023-24 की पहली तिमाही में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा बजट से अधिक अधिशेष हस्तांतरण के कारण गैर-कर राजस्व में उच्च वृद्धि के कारण है। [4] हालाँकि, यह आंशिक रूप से निम्न कर संग्रह और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों द्वारा ऑफसेट था। [5] 2023-24 की दूसरी तिमाही में कर राजस्व में बढ़ोतरी के साथ, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 34.4 प्रतिशत तक सुधरी (चार्ट 2 ए और बी)।

चार्ट 1: पहली छमाही में कुल प्राप्तियाँ और व्यय

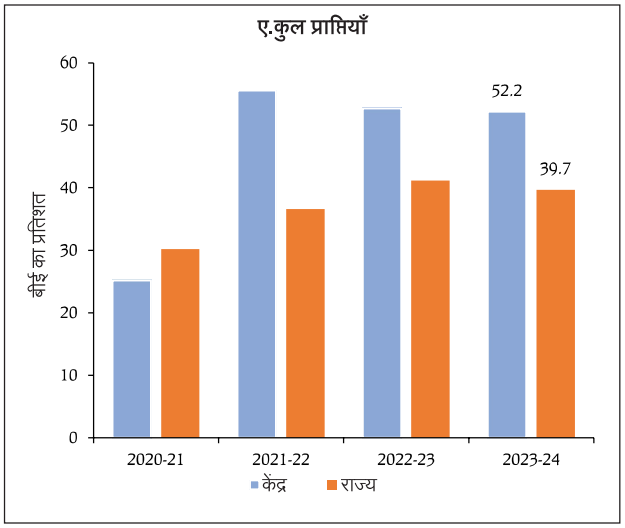

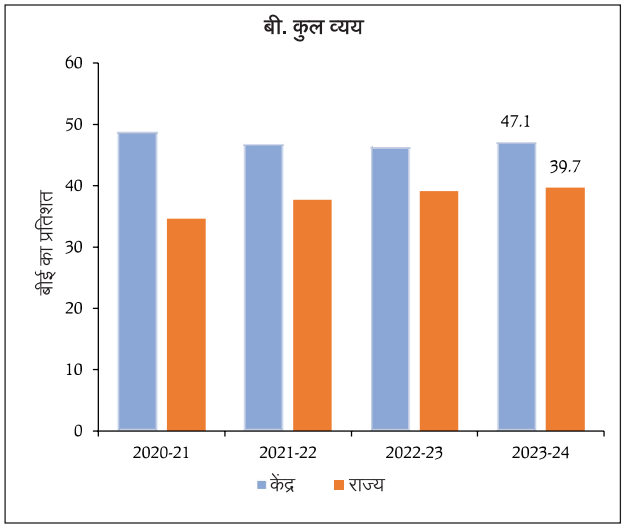

स्रोत: लेखा महानियंत्रक (सीजीए); और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।

[4] 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को ₹87,416 करोड़ का अधिशेष हस्तांतरित किया, जो पिछले वर्ष हस्तांतरित राशि (₹30,307 करोड़) और भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभांश/अधिशेष हस्तांतरण के तहत बजटीय राशि से अधिक है । और केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय संस्थान (₹48,000 करोड़)।

[5] गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण और अग्रिम की वसूली और विविध पूंजी प्राप्तियां (अर्थात् विनिवेश और अन्य प्राप्तियां) शामिल हैं।

चार्ट 2: केंद्र की प्राप्तियों का त्रैमासिक ब्यौरा

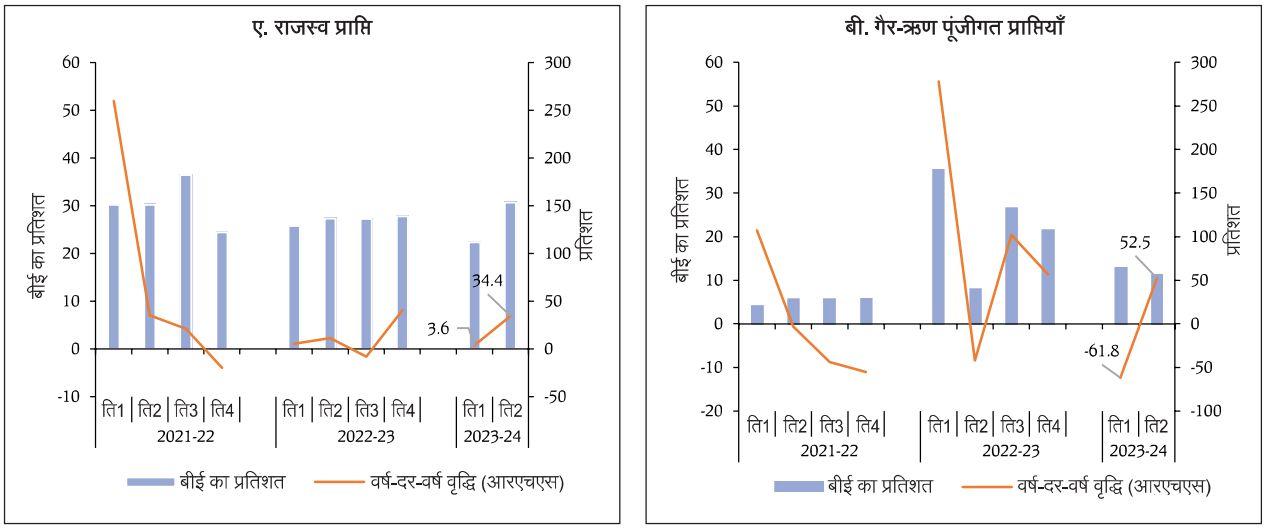

स्रोत: लेखा महानियंत्रक (सीजीए); और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज़।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (2022-23 की पहली छमाही में 26.2 प्रतिशत की प्रशंसनीय वृद्धि से अधिक)। यह वृद्धि क्यू 1:2023-24 और क्यू 2:2023-24 में क्रमशः 15.3 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत तक फैली हुई थी। कर राजस्व, जो एच 1:2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 81 प्रतिशत था, ने क्रमशः क्यू 1:2023-24 और क्यू 2:2023-24 में 22.4 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। हालाँकि, राज्यों की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ [6] में क्यू 1:2023-24 में संकुचन देखा गया, लेकिन क्यू 2:2023-24 में मजबूत सुधार दर्ज किया गया (चार्ट 3 ए और बी)।

चार्ट 3 : राज्यों की प्राप्तियों का त्रैमासिक ब्यौरा

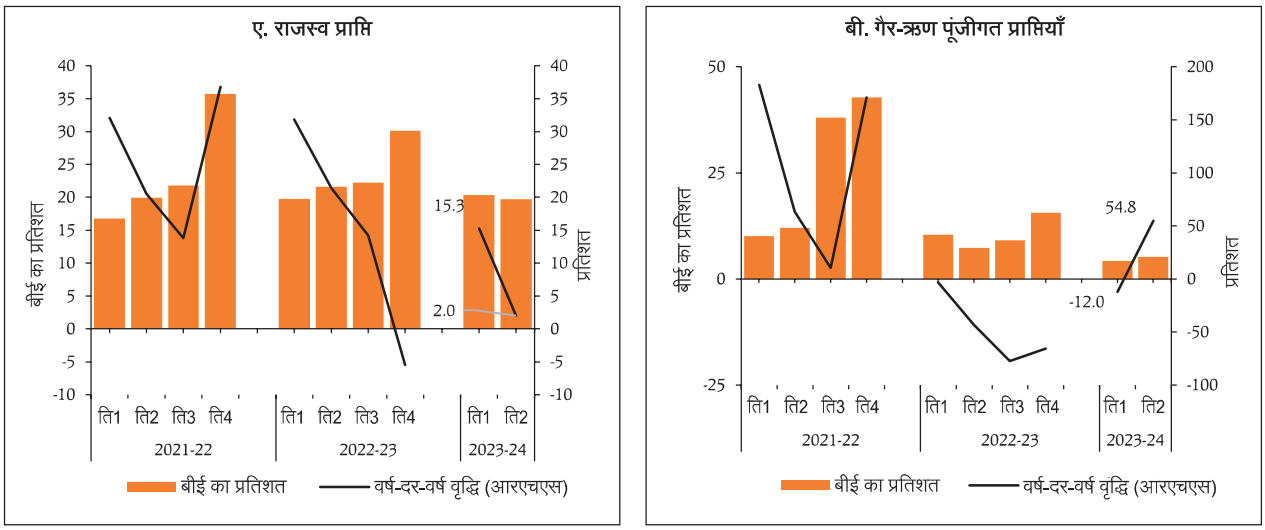

स्रोत: लेखा महानियंत्रक (सीजीए); और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

[6] राज्यों की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में उनके द्वारा अधीनस्थ/अर्धराज्यीय संस्थाओं को वितरित ऋणों और अग्रिमों की वसूली और अन्य विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।

चार्ट 4: त्रैमासिक प्रत्यक्ष कर संग्रहण

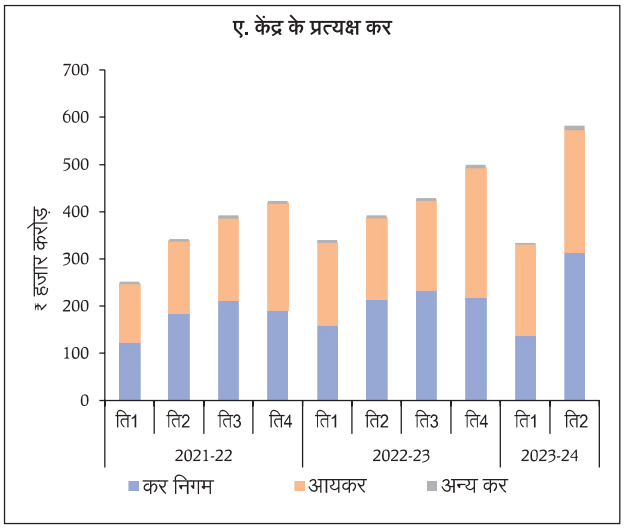

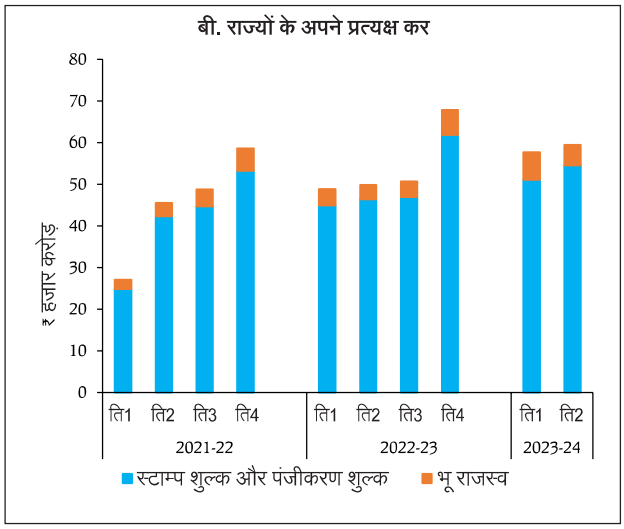

स्रोत: लेखा महानियंत्रक (सीजीए); और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।

वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसके कारण निगम कर और आयकर संग्रह में क्रमशः 20.2 प्रतिशत और 31.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023-24 की पहली तिमाही में, कॉर्पोरेट कर संग्रह में 13.9 प्रतिशत की गिरावट के कारण केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 2023-24 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल आधार पर 48.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह दोनों। अगस्त-सितंबर 2023-24 में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि का अनुभव हुआ, जिससे अप्रैल-जुलाई के दौरान देखी गई सुस्ती को दूर करने में मदद मिली। एच 1:2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह को बढ़े हुए अनुपालन, उच्च अग्रिम कर संग्रह और कर आधार के विस्तार (चार्ट 4ए) से लाभ हुआ।[7, 8, 9] दूसरी ओर, 2023-24 की पहली छमाही में केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह को छोड़कर प्रमुख मदों में मजबूत वृद्धि हुई, जिसमें आंशिक रूप से संकुचन का अनुभव हुआ। मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती।[10]

राज्यों के स्वयं के प्रत्यक्ष कर संग्रह (जिसमें भूमि राजस्व और स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं) ने एच 1:2023-24 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में क्यू 1:2023-24 में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद क्यू 2:2023-24 में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 4बी)।

जीएसटी संग्रह (केंद्र प्लस राज्य) लगातार 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रहा है और 2023-24 की पहली छमाही के दौरान औसतन ₹1.7 लाख करोड़ रहा, जबकि 2022-23 की पहली छमाही के दौरान यह औसतन ₹1.5 लाख करोड़ था। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ-साथ अनुपालन में भी वृद्धि हुई है। जीएसटी संग्रह में साल-दर-साल आधार पर क्यू 1:2023-24 में 11.6 प्रतिशत और क्यू 2:2023-24 में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 5)।

राज्यों के लिए, राज्यों के जीएसटी के उच्च और स्थिर संग्रह [अर्थात, एसजीएसटी] (बढ़ती मांग और अधिक अनुपालन के कारण), और केंद्र से कर हस्तांतरण (उच्च उछाल के कारण) ने राजस्व में वृद्धि में योगदान दिया। एच 1:2023-24 में, राज्यों को असाइनमेंट (यानी, राज्यों को नियमित किस्त) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एच 1 में प्राप्त लगभग 45 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि के शीर्ष पर है। :2022-23. विशेष रूप से, जून 2023 में, सरकार ने राज्यों को

[7] प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), 1 नवंबर, 2023।

[8] पीआईबी, 26 अक्टूबर, 2023।

[9] पीआईबी, 18 सितंबर, 2023।

[10] पेट्रोल के लिए, उत्पाद शुल्क में कटौती ₹8 प्रति लीटर थी, जबकि डीजल के मामले में, 22 मई, 2022 से उत्पाद शुल्क में ₹6 प्रति लीटर की कटौती की गई थी।

चार्ट 5: जीएसटी संग्रह

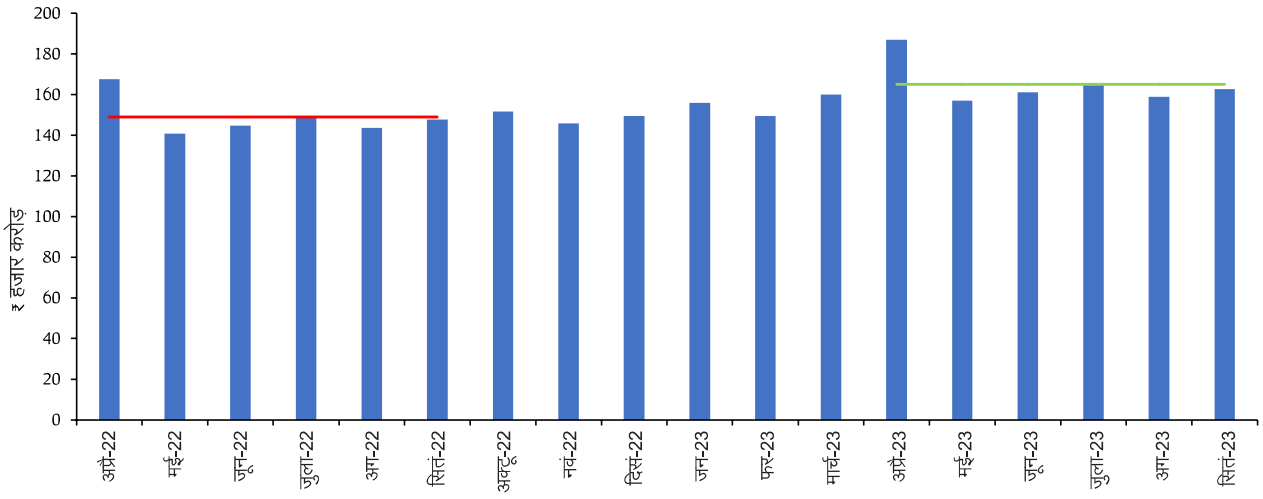

नोट: लाल और हरी रेखा उन महीनों के औसत जीएसटी संग्रह को दर्शाती है।
स्रोत: पीआईबी विज्ञप्ति, भारत सरकार।

पूंजीगत व्यय में तेजी लाने, उनके विकास संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए कर हस्तांतरण की एक अग्रिम किस्त जारी की थी (चार्ट 6 ए और बी)।[11]

बीई के प्रतिशत के अनुसार, केंद्र से एच 1:2023-24 में राज्यों को कर हस्तांतरण 2023-24 के लिए बजटीय राशि का 44.6 प्रतिशत था (एच 1:2022-23 में 46.1 प्रतिशत के मुकाबले)। केंद्र द्वारा अधिक और समय पर कर हस्तांतरण

चार्ट 6: एसजीएसटी का त्रैमासिक प्रदर्शन और केंद्र से कर हस्तांतरण

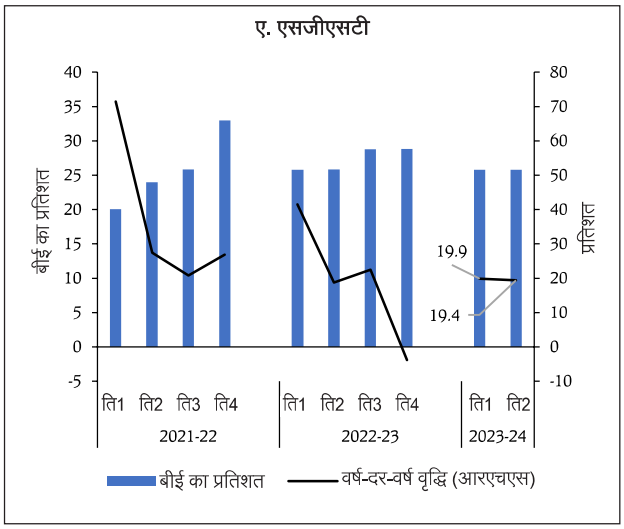

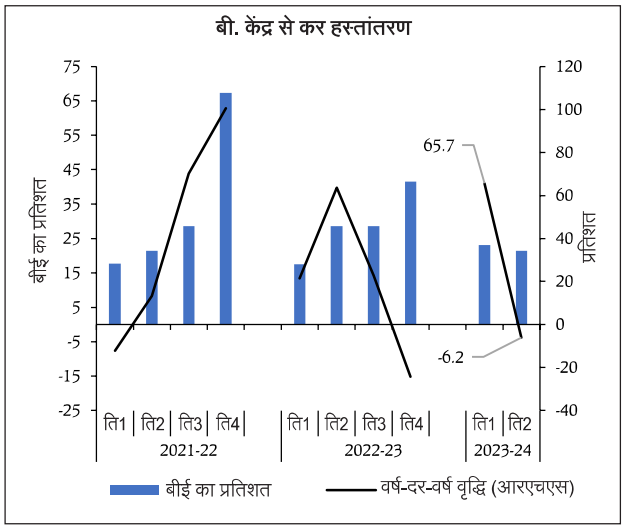

स्रोत: सीजीए और सीएजी।

[11] पीआईबी, 12 जून, 2023।

राज्यों को संसाधनों, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के बेहतर खर्च की योजना बनाने में सक्षम बनाता है, साथ ही भारतीय राज्यों में निहित क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन 12 के मुद्दे को भी संबोधित करता है (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: क्षैतिज असंतुलन: राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का क्लब अभिसरण विश्लेषण

राज्यों के बीच विविधता के कारण, उपराष्ट्रीय इकाइयों के बीच क्षैतिज वित्तीय असंतुलन अपेक्षित है। समानीकरण हस्तांतरण क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस संदर्भ में, राजकोषीय अंतर को मापना और असंतुलन के प्रक्षेप पथ का मानचित्रण करना राजकोषीय हस्तांतरण को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षैतिज असमानताओं को मापने और समय के साथ असमानताओं की गतिशीलता को समझने में अभिसरण विश्लेषण उपयोगी हो सकता है। अभिसरण परिकल्पना कहती है कि गरीब क्षेत्र अमीर क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं और अंततः उनकी बराबरी कर लेते हैं। क्लब अभिसरण विश्लेषण क्षेत्रों के भीतर और उनके बीच अलग-अलग अभिसरण पैटर्न प्रकट कर सकता है। यह मानता है कि सभी क्षेत्र एक ही सामान्य स्तर पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी विशेषताओं और विकास पथों के आधार पर विभिन्न स्थिर समूहों या 'क्लबों' में परिवर्तित हो सकते हैं। यह उन विशिष्ट कारकों और विशेषताओं की पहचान करने में मदद करता है जो क्षेत्रों को अलग-अलग रास्तों पर चलने और विभिन्न स्थिर आय या विकास स्तरों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं।

2001-2022 तक 16 भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) के लिए क्लब अभिसरण परिकल्पना की जांच फिलिप्स और सुल (2007, 2009) के बाद 'लॉग टी-टेस्ट' का उपयोग करके की गई थी। परिणामों ने संकेत दिया कि, सभी 16 भारतीय राज्यों के लिए, समग्र स्तर पर भिन्नता है। हालाँकि, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम [13] से पता चलता है कि राज्य दो अलग-अलग क्लबों में बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 8 राज्य होते हैं। क्लब 1 का औसत प्रति व्यक्ति एसओटीआर क्लब 2 (चार्ट बी 1 और तालिका बी 1.ए) से अधिक है।

जैसा कि गुणांक द्वारा दर्शाया गया है, अभिसरण की गति, क्लब 2 की तुलना में क्लब 1 के लिए तेज़ है, यह दर्शाता है कि अमीर राज्य गरीब राज्यों की तुलना में तेज़ी से अभिसरण कर रहे हैं।

क्लब गठन के निर्धारकों की खोज के लिए, निम्नलिखित चर के साथ एक द्विआधारी प्रोबिट मॉडल का अनुमान लगाया गया था: प्रारंभिक सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक कारक जैसे प्रारंभिक प्रति व्यक्ति आय, प्रारंभिक साक्षरता दर, जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि। कुल मिलाकर, अनुमान बताते हैं कि जीएसडीपी में कृषि की कम हिस्सेदारी वाले राज्यों के उच्च औसत स्वयं के कर राजस्व वाले क्लब में होने की अधिक संभावना है (तालिका बी1.बी)। प्रति व्यक्ति आय का प्रारंभिक स्तर और साक्षरता दर द्वारा दर्शाए गए सामाजिक कारक भी किसी क्लब की सदस्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

चार्ट बी1: औसत प्रति व्यक्ति राज्यों का अपना कर राजस्व

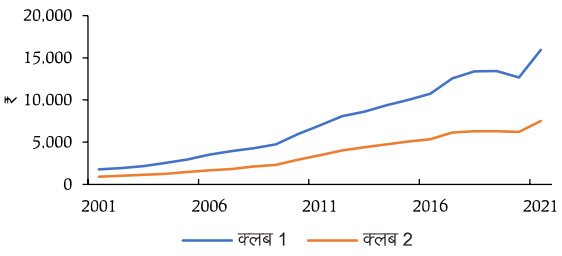

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संक्षेप में, क्लब अभिसरण विश्लेषण राज्यों के बीच बढ़ती खाई का सुझाव देता है। गरीब राज्य संरचनात्मक और प्रारंभिक सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थितियों से प्रभावित हैं। हालाँकि, समानीकरण हस्तांतरण राज्यों की राजकोषीय क्षमता में सुधार कर सकता है और साथ ही क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को भी संबोधित कर सकता है।

सारणी बी1.ए: राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का क्लब अभिसरण

	सभी राज्य	क्लब 1	क्लब 2
राज्यों की संख्या	16	8	8
गुणक	-0.18	0.24	0.06
टी स्टेट	-5.85	4.45	1.40

सारणी बी1.बी: क्लब गठन का निर्धारण करने वाले कारक

विवरणात्मक परिवर्ती	गुणक	मानक त्रुटि
कृषि का एलएन हिस्सा	-2.65***	0.40
एलएन प्रारंभिक प्रति व्यक्ति आय	1.63***	0.40
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि	0.28**	0.12
एलएन प्रारंभिक साक्षरता दर	3.01**	1.45
स्थिर	-21.49***	4.90

प्रेक्षणों की संख्या = 306, t=21, n=16.
एलआर ची2 (4) = 214.27, संभावना > ची2 = 0.0
छद्म आर2 = 0.5052
नोट: ***: पी < 0.01, **: पी<0.05.

संदर्भ:

Phillips, P. C., & Sul, D. (2007). Transition Modeling and Econometric Convergence Tests. *Econometrica*, 75(6), 1771-1855.

[12] क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन राज्यों की अपने कर आधार से संसाधन जुटाने की क्षमताओं में असमानता को संदर्भित करता है।

[13] फिलिप्स और सुल का एल्गोरिदम स्वचालित रूप से उन इकाइयों को समूहित करता है जो मनमाने ढंग से पूर्व-चयन से बचते हुए समान रूप से एकत्रित होती हैं। यह उनके डेटा के आधार पर मुख्य इकाइयों की पहचान करता है और शेष इकाइयों को उपयुक्त क्लबों को सौंपता है। अपने निर्दिष्ट क्लब के भीतर उच्च अवशिष्ट भिन्नता वाली इकाइयों को बेहतर फिट के लिए फिर से सौंपा गया है। यह गतिशील प्रक्रिया विविध अभिसरण गति की अनुमति देती है और डेटा में छिपे पैटर्न को उजागर करती है।

चार्ट 7: केंद्र सरकार का गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियाँ

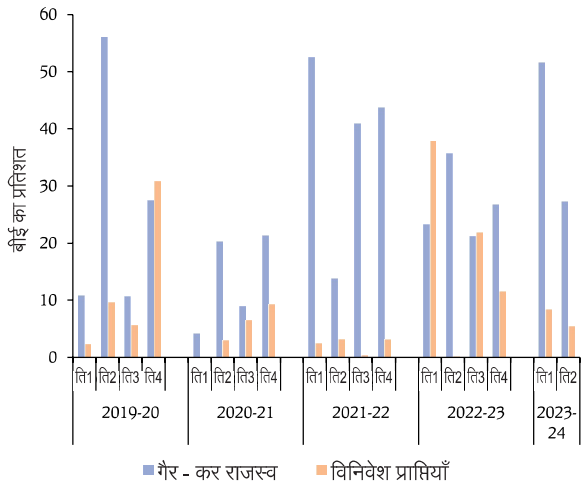

स्रोत: सीजीए

रिज़र्व बैंक द्वारा बजटीय अधिशेष हस्तांतरण से अधिक के कारण 2023-24 की पहली तिमाही में केंद्र के गैर-कर राजस्व में वृद्धि हुई, लेकिन लाभांश और मुनाफे से राजस्व में वृद्धि के कारण 2023-24 की दूसरी तिमाही में 14.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। आर्थिक सेवाओं से राजस्व में संकुचन से भरपाई।[15] विनिवेश के मोर्चे पर, ₹51,000 करोड़ के बजटीय विनिवेश लक्ष्य का लगभग 14 प्रतिशत एच 1:2023-24 में जुटाया गया, जबकि एच 1:2022-23 में यह 38 प्रतिशत था (चार्ट 7)।[16]

बी. व्यय

वर्ष 2023-24 (बीई) में, केंद्र सरकार के कुल व्यय में 7.5 प्रतिशत[17] की वृद्धि का बजट लगाया गया था, जो 2022-23 (आरई) में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम था। राजस्व व्यय वृद्धि को 1.3 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़ने के लिए बजट किया गया था जबकि पूंजीगत व्यय वृद्धि 37.4 प्रतिशत आंकी गई थी.[18] एच1:2023-24 में, केंद्र का कुल व्यय 2023-24 के बजट अनुमानों का 47.1 प्रतिशत (2021-22 और 2022-23 में बजट अनुमानों का 46.7 और 46.2 प्रतिशत) था, क्रमशः)। राजस्व व्यय 2023-24 बजट अनुमान का 46.5 प्रतिशत (2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 47.7 और 46.3 प्रतिशत की तुलना में) प्राप्त हुआ, जबकि पूंजीगत व्यय 2023-24 बजट अनुमान का 49.0 प्रतिशत था (बजट अनुमान का 41.4 और 45.7 प्रतिशत क्रमशः 2021-22 और 2022-23 के दौरान देखा गया)।

केंद्र सरकार द्वारा एच 1:2023-24 में पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाया गया है जो अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए अच्छा संकेत है। एच 1:2023-24 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालयों का कुल पूंजीगत व्यय में 75 प्रतिशत से अधिक का योगदान था (चार्ट 8)।

चार्ट 8: 2022-23 की पहली छमाही और 2023-24 की पहली छमाही में प्रमुख मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय

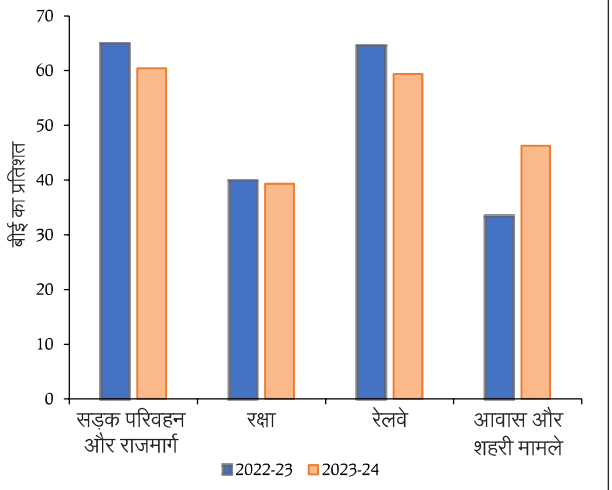

स्रोत: सीजीए

[14] 'लाभांश और मुनाफे' से गैर-कर राजस्व 2023-24 में बजटीय गैर-कर राजस्व का 30.2 प्रतिशत है।

[15] आर्थिक सेवाओं से गैर-कर राजस्व में कृषि और संबद्ध गतिविधियां (कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियां, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रेडिंग के लिए शुल्क, आदि), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (केंद्रीय जल की प्राप्तियां) शामिल हैं। आयोग और केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे आदि), संचार (दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियां शामिल हैं) आदि। आर्थिक सेवाओं से गैर-कर राजस्व बजटीय गैर-कर का 50.3 प्रतिशत है। 2023-24 में राजस्व।

[16] एच 1:2023-24 के दौरान, सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के रूप में ₹6,950 करोड़ जुटाए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹24,590 करोड़ जुटाए गए थे।

[17] 2022-23 (पीए) में, 2023-24 (बीई) में केंद्र सरकार का कुल व्यय भी 7.5 प्रतिशत बढ़ने का बजट है।

[18] पूंजीगत परिव्यय (अर्थात, ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय) को 2022-23 (आरई) में 16.03 प्रतिशत की वृद्धि के शीर्ष पर, 2023-24 में 35.0 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया था।

चार्ट 9: दूसरी छमाही में व्यय वृद्धि

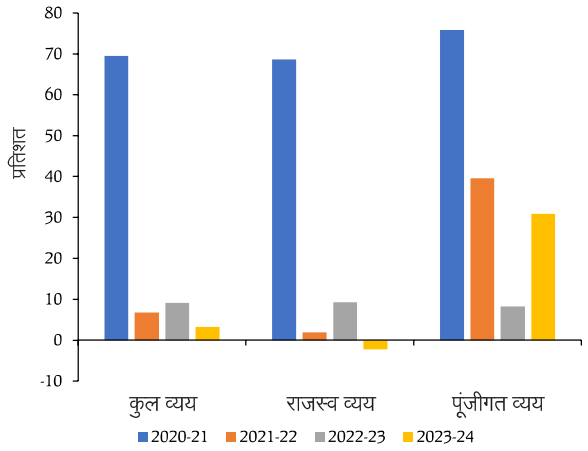

नोट: 2023-24 के लिए व्यय वृद्धि सितंबर 2023 तक वास्तविक और 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ-साथ अनुदान की पहली अनुपूरक मांग में व्यय प्रस्तावों पर आधारित निहित वृद्धि दर है।

स्रोत: सीजीए; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र[19] के दौरान 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग (एसडीजी-I) का पहला बैच संसद के समक्ष रखा था, जिसमें ₹58,378 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय शामिल था.[20] आगे बढ़ते हुए, H2:2023-24 में, कुल व्यय वृद्धि में मामूली वृद्धि होने की संभावना है, मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि (चार्ट 9) के पीछे।

तिमाही रुझानों से संकेत मिलता है कि राजस्व व्यय क्यू 1:2023-24 में स्थिर रहने के बाद क्यू 2:2023-24 में बढ़ गया। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय ने क्यू 1:2023-24 और क्यू 2:2023-24 दोनों में मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार) प्रदर्शित की, जिसमें पूर्व में वृद्धि बाद की तुलना में अधिक थी (चार्ट 10 ए और बी)।

केंद्र सरकार की प्रमुख सब्सिडी, जिसमें भोजन, ईंधन और उर्वरक शामिल हैं, एच 1:2023-24 में BE का 55.1 प्रतिशत था, जबकि एच 1:2022-23 में BE का 62.6 प्रतिशत था। 2023-24 की पहली छमाही में प्रमुख सब्सिडी पर उर्वरक और खाद्य सब्सिडी का हिस्सा 53.4 प्रतिशत और 46.1 प्रतिशत था, जो

चार्ट 10: केंद्र सरकार का त्रैमासिक व्यय

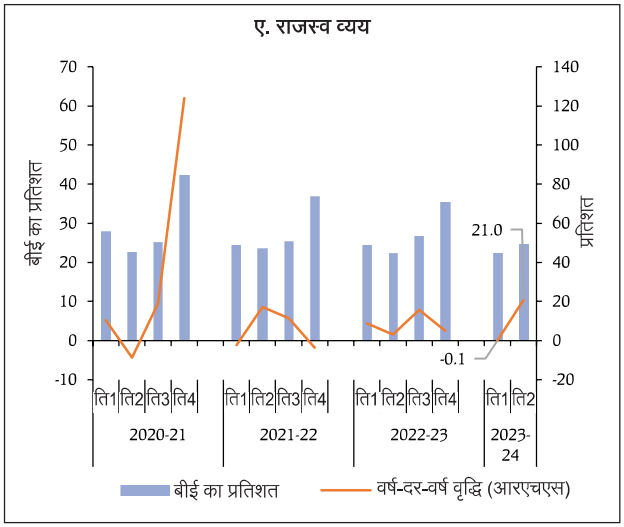

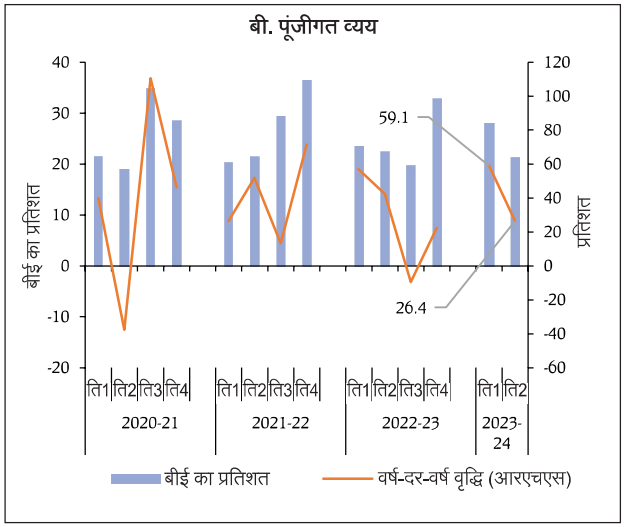

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

[19] दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित।

[20] दिसंबर 2022 में संसद के समक्ष रखे गए 2022-23 के एसडीजी-I में ₹3.25 लाख करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल था।

चार्ट 11: केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सब्सिडी पर त्रैमासिक व्यय

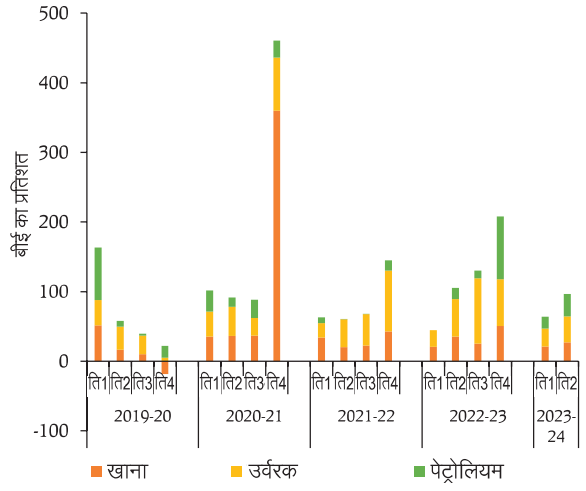

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमशः 41.1 प्रतिशत और 58.4 प्रतिशत था (चार्ट 11)।

वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में राज्यों के राजस्व व्यय की वृद्धि क्रमशः 7.8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत थी, जो 2022-23 की इसी तिमाही में दर्ज की गई वृद्धि से काफी कम थी। फिर भी, पिछले वर्ष के व्यय व्यवहार के अनुरूप, राज्यों ने एच 1:2023-24 में अपने बजटीय राजस्व व्यय का 41.0 प्रतिशत समाप्त कर लिया है (एच 1:2022-23 में 41.5 प्रतिशत की तुलना में)। दूसरी ओर, राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाया गया जिसके परिणामस्वरूप एच 1:2023-24 में 47.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, क्यू 1:2023-24 और क्यू 2:2023-24 में 72.4 प्रतिशत और 33.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रमश। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी परिव्यय (पूंजीगत व्यय ऋण और अग्रिम घटाकर) ने एच 1:2023-24 में 52.6 प्रतिशत की और भी अधिक वृद्धि दर्ज की, जबकि एच 1:2022-23 के दौरान 2.9 की मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 12 ए और बी))।

III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण

केंद्र सरकार

ए. राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार ने 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के जीएफडी के लिए बजट रखा था जो 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के मध्यम अवधि के जीएफडी लक्ष्य के अनुरूप है। 2023-24 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र सरकार का जीएफडी बीई का 39.3 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 37.3 प्रतिशत के जीएफडी से थोड़ा अधिक था, जिसका कारण केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय की फ्रंट-

चार्ट 12: राज्य सरकारों का त्रैमासिक व्यय

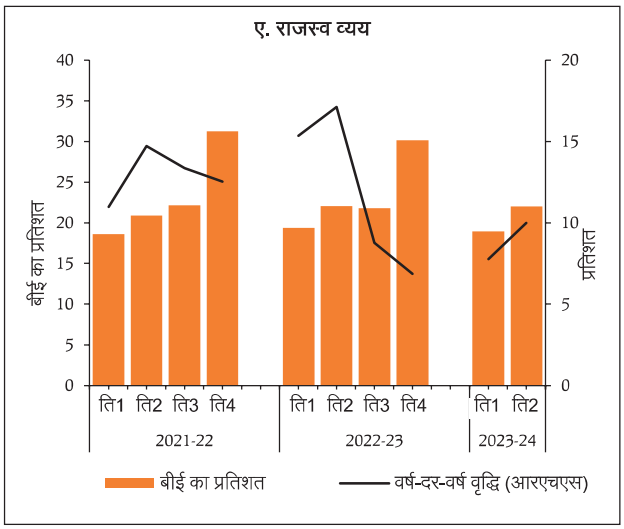

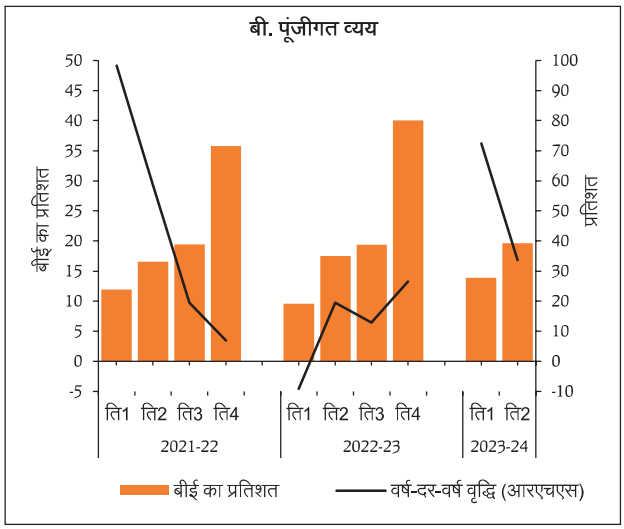

स्रोत: सीजीए; और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

चार्ट 13: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा

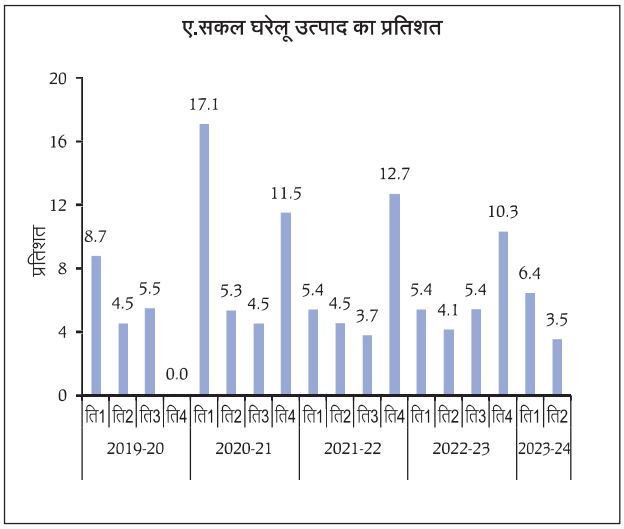

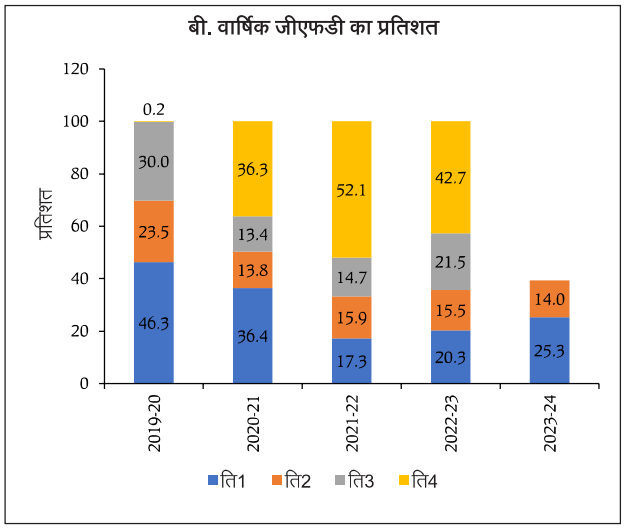

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

लोडिंग थी। सरकार। केंद्र सरकार द्वारा मजबूत कर संग्रह। क्यू 2:2023:24 में मजबूत कर संग्रह में राजकोषीय घाटा इस अवधि के दौरान बीई के 14.0 प्रतिशत पर था (चार्ट 13 ए और बी) (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2: केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में बदलता तिमाही रुझान

केंद्र सरकार के जीएफडी में तिमाही रुझान में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 2020-21 से पहले, पहली तिमाही में जीएफडी आमतौर पर पूरे वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत पार कर जाती थी, यहां तक कि 2017-18 में 74.7 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि चौथी तिमाही में न्यूनतम राजकोषीय घाटा या कभी-कभार राजकोषीय घाटा भी देखा गया। अधिशेष, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष की पहली छमाही में अधिक उधार लेने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, जीएफडी के तिमाही वितरण में उलटफेर हुआ है, जिसका मुख्य कारण कर और गैर-कर राजस्व का समान वितरण है।

वर्ष 2017-18 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के साथ, अप्रत्यक्ष कर तिमाहियों में अधिक समान रूप से वितरित हो गए हैं। प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी भी क्यू 1 में बढ़ी है जिसका श्रेय केंद्र द्वारा लागू बेहतर कर अनुपालन उपायों को दिया जा सकता है (चार्ट बी 2.ए)। गैर-कर राजस्व के अंतर्गत, 2021-22 से रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष में जुलाई-जून से अप्रैल-मार्च में परिवर्तन के साथ, केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण अब अगस्त के बजाय मई के महीने में जमा किया जाता है। इस प्रकार, 2021-22 के बाद से, केंद्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में गैर-कर राजस्व का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा प्राप्त हो रहा है (चार्ट बी 2.बी)।

साथ ही, कुल व्यय थोड़ा विपरीत दिशा में चला गया है और 2020-21 से 2022-23 के दौरान क्यू 4 में किए गए कुल व्यय का एक तिहाई से अधिक हो गया है, जबकि 2014-20 के दौरान यह औसत 23.5 प्रतिशत था (चार्ट बी2.सी)। परिणामस्वरूप, पहली दो तिमाहियों में जीएफडी में भारी कमी आई है; क्यू 4 में जीएफ़डी अब पूरे वर्ष जीएफ़डी (चार्ट बी 2.डी) का सबसे बड़ा हिस्सा है।

कर राजस्व का प्रारंभिक प्रवाह अधिक सटीक बजट और पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करता है क्योंकि सरकारी एजेंसियां उपलब्ध धन के अधिक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर अपने व्यय की योजना बना सकती हैं, जिससे बजटीय कमी का जोखिम कम हो जाता है। इससे केंद्र सरकार को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्यों को कर

(जारी...)

चार्ट बी 2: केंद्र के कर राजस्व का त्रैमासिक वितरण

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

हस्तांतरण की अग्रिम किश्तें देने की भी अनुमति मिल गई है। पूरे वर्ष अधिक सुसंगत नकदी प्रवाह से सरकार की अल्पकालिक उधार पर निर्भरता कम हो जाती है और कम ब्याज भुगतान के कारण लागत बचत होती है।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए बजटीय शुद्ध बाजार उधार का 61.8 प्रतिशत पूरा कर लिया। केंद्र सरकार के जीएफडी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के उपयोग के बाद बाजार उधार लिया गया। 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए अपने उधार लक्ष्य पर टिके रहने का केंद्र का निर्णय सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के उसके विश्वास का संकेत देता है। इसका श्रेय केंद्र के कर राजस्व को जाता है जो गैर-कर मोर्चे पर अनुमान से अधिक संग्रह के अलावा मजबूत गति से बढ़ रहा है।

राज्य सरकार

ए. राजकोषीय घाटा

राज्यों ने 2023-24 (बीई) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत समेकित जीएफडी का बजट रखा था, जो 2022-23 (आरई) में 3.4 प्रतिशत से कम है। 2023-24 के दौरान, राज्यों ने क्यू 1 में अपने बजटीय जीएफ़डी का कम अनुपात समाप्त कर लिया है, जबकि क्यू 2 में, जीएफ़डी अधिक रहा है। तदनुसार, 2023-24 के उत्तरार्ध में राज्यों के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 69.9 प्रतिशत से घटाकर उनके बजटीय जीएफडी का 60.2 प्रतिशत कर दिया गया है (चार्ट 14 ए और बी)।

चार्ट 14: राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

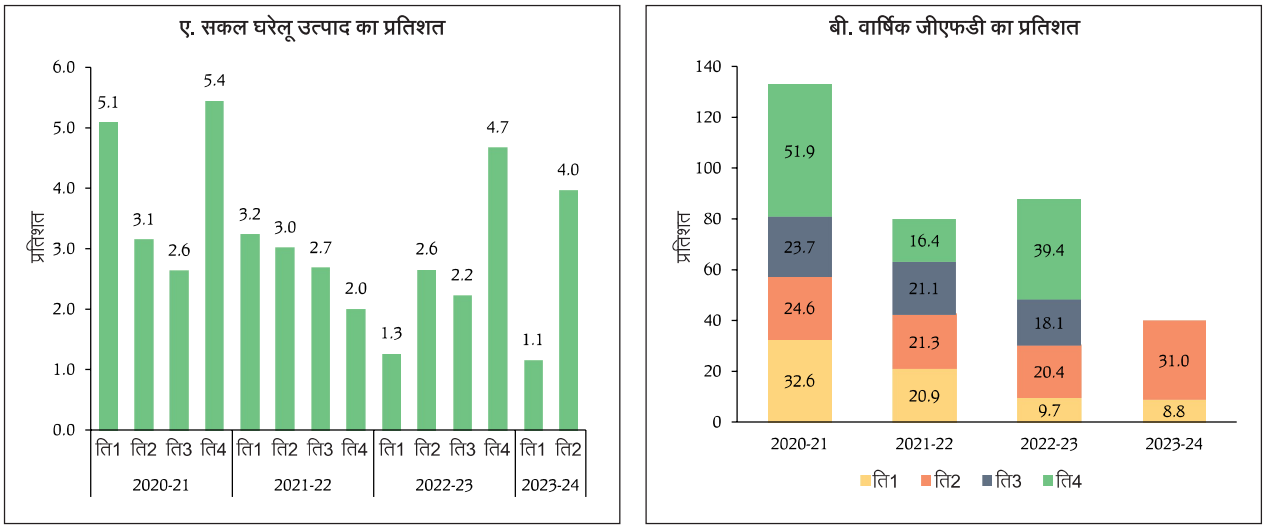

स्रोत: सीएजी; और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

व्यय की गुणवत्ता [राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात [21] द्वारा मापी गई] में एच1:2023-24 में सुधार हुआ, जिसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर दिए गए उच्च जोर को दिया गया। [22] इसी तर्ज पर, महामारी के बाद की अवधि में राज्यों की व्यय गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। 2023-24 की क्यू 1 और क्यू 2 में, उनका RECO अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 11.6 और 7.2 से घटकर क्रमशः 7.3 और 5.6 हो गया (चार्ट 15 ए और बी)।

चार्ट 15: केंद्र और राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा और व्यय की गुणवत्ता

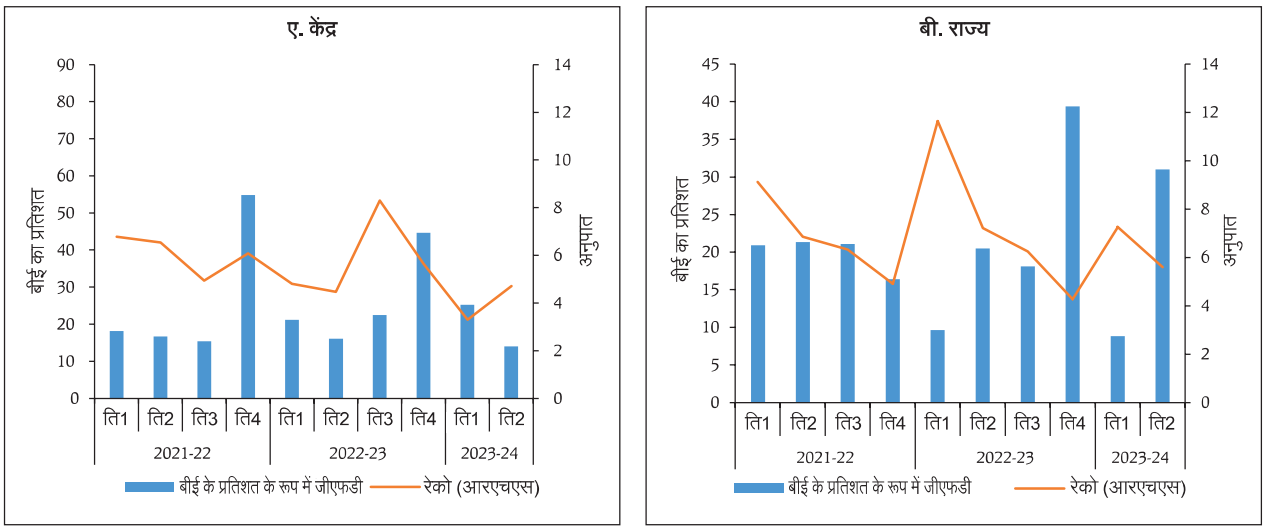

स्रोत: सीजीए: सीएजी; केंद्र और राज्यों के बजट दस्तावेज़।

[21] आरईसीओ अनुपात में गिरावट व्यय की गुणवत्ता में सुधार और इसके विपरीत का संकेत देती है।

[22] एच 1:2023-24 में, केंद्र के लिए RECO अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पंजीकृत 4.6 की तुलना में 3.9 था।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

एच 1:2023-24 के दौरान राज्यों की शुद्ध बाजार उधारी में साल-दर-साल 23.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और यह उनके BE का केवल 24.8 प्रतिशत (एच 1:2022-23 के दौरान 33.7 प्रतिशत) रहा। 2023-24 की पहली छमाही में आठ राज्यों की शुद्ध उधारी शून्य या नकारात्मक थी। हालाँकि, सकल बाज़ार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 9.0 प्रतिशत अधिक था (चार्ट 16 ए और बी)।

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय आवास में एच 1:2023-24 के दौरान 61.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। राज्यों द्वारा वेज एंड मीन्स एडवांस (डब्ल्यूएमए) और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के तहत प्राप्त औसत राशि में क्रमशः 14.9 प्रतिशत और 115.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ओवरड्राफ्ट (ओडी) लाभ में 15.8 प्रतिशत की गिरावट आई। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में एच 1:2023-24 में डबल्यूएमए के अपने दैनिक उपयोग में कमी की (चार्ट 17 ए और बी)।

चार्ट 16: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बाज़ार उधार

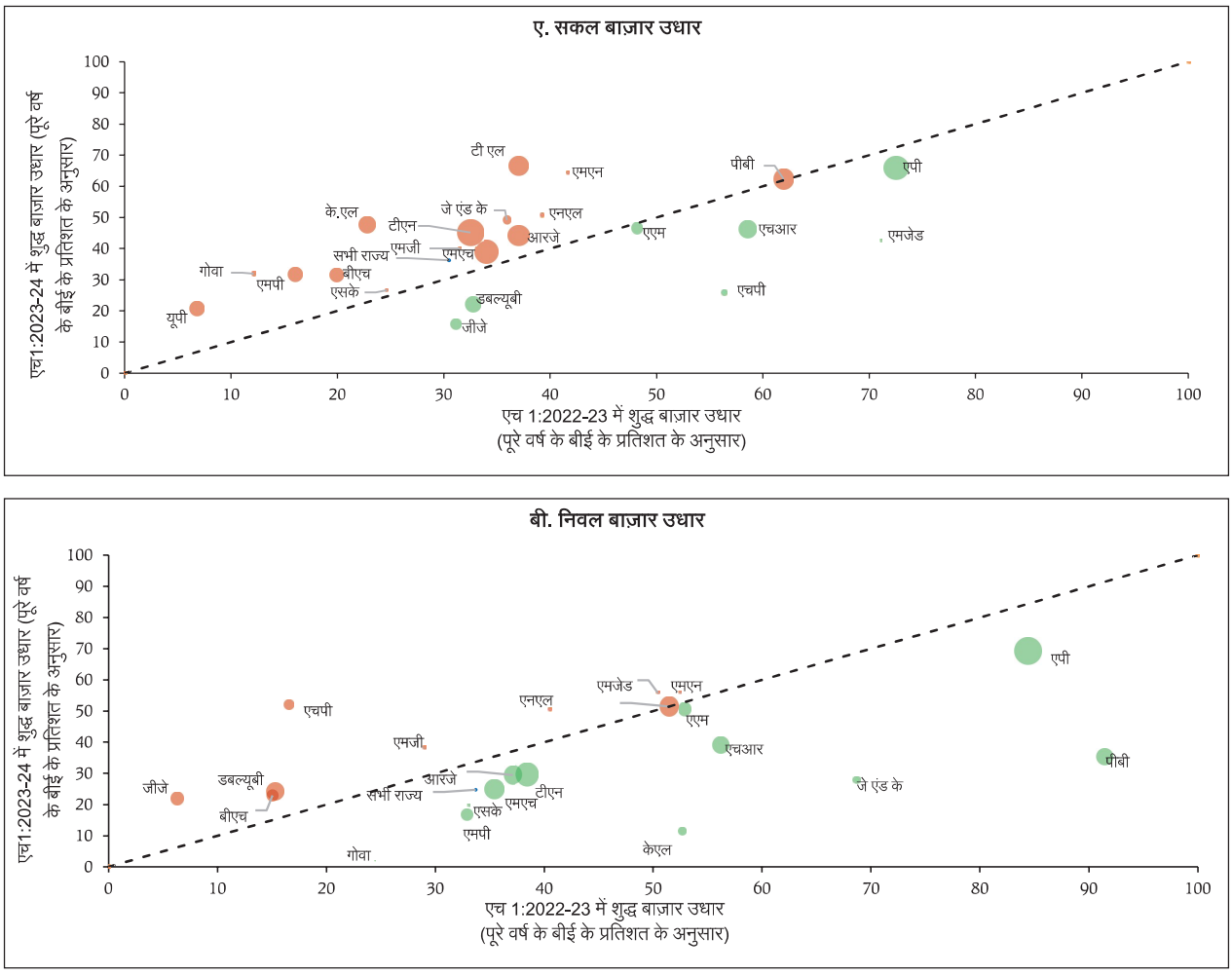

टिप्पणियाँ: 1. बुलबुले का आकार एच 1:2023-24 बाजार उधार में राज्य की हिस्सेदारी से मेल खाता है।
2. 45-डिग्री रेखा कोई परिवर्तन नहीं दर्शाती है।

स्रोत: आरबीआई; और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बजट दस्तावेज़।

चार्ट 17: रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय आवास

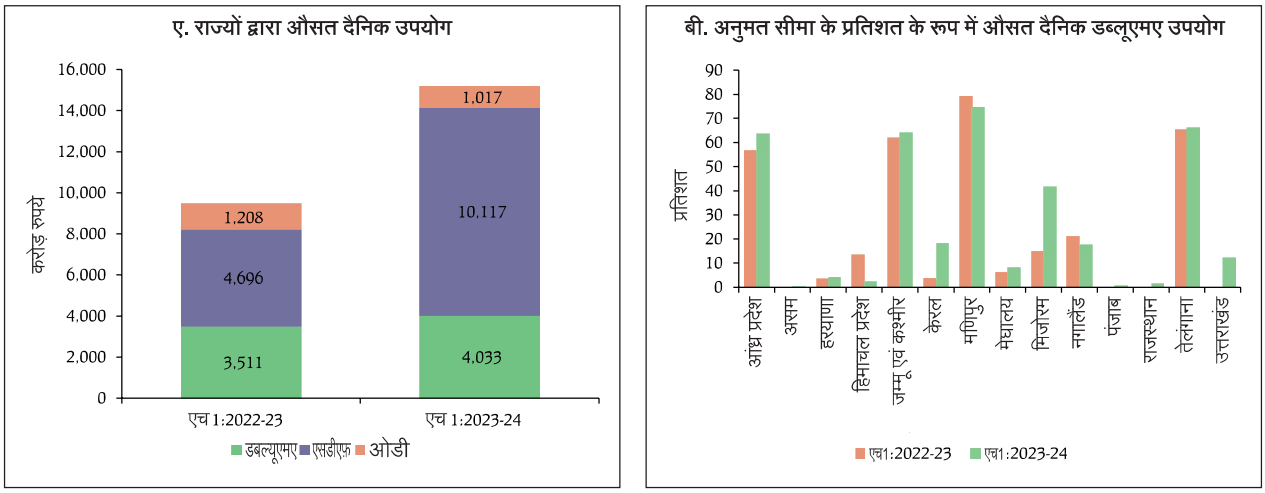

स्रोत: आरबीआई बुलेटिन कई मुद्दे; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

IV. सामान्य सरकारी वित्त

वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य सरकारी जीएफडी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 8.6 प्रतिशत है, जबकि 2022-23 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत है। सामान्य सरकार पर समय पर राजकोषीय डेटा उपलब्ध कराने के प्रयास को जारी रखते हुए, सामान्य सरकार की तिमाही राजकोषीय स्थिति को क्यू 2:2023-24 तक संकलित किया गया है। केंद्र और राज्यों द्वारा बेहतर राजस्व संग्रहण ने सामान्य सरकारी जीएफडी को 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष के रुझानों के अनुरूप बनाए रखा। आगे बढ़ते हुए, जबकि कर संग्रह एच 2 में उछालपूर्ण रहने की उम्मीद है, केंद्र और राज्यों द्वारा व्यय में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप क्यू 3 और क्यू 4 (अनुमानित) में सामान्य सरकारी घाटा 8.2 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत हो सकता है। क्रमशः (चार्ट 18)।

चार्ट 18: सामान्य सरकारी सकल राजकोषीय घाटा: वास्तविक और अनुमानित

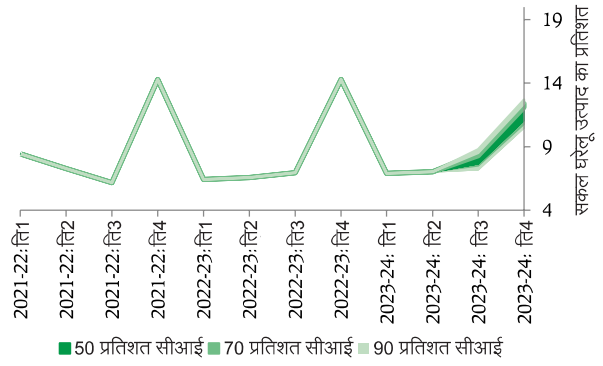

नोट : 1. गाढ़ा हरा छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल (सीआई) का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम घने हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत आत्मविश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई सीमा में होंगे।

2. वास्तविक संयुक्त जीपीडी-जीडीपी अनुपात केंद्र और 25 राज्यों के लिए है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

V. निष्कर्ष

वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में केंद्र और राज्यों की संयुक्त वित्तीय स्थिति मजबूत रही। केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों में मजबूत कर संग्रह दर्ज किया, जो अर्थव्यवस्था की निरंतर वसूली, बेहतर कर प्रशासन और प्रशासन के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार को दर्शाता है। कम विनिवेश प्राप्तियों की भरपाई गैर-कर राजस्व में तेज बढ़ोतरी से होने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलने वाला उच्च लाभांश है। व्यय के मोर्चे पर, पूंजीगत व्यय पर जोर देने से केंद्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित हुआ है। 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के अपने जीएफडी लक्ष्य को दोहराकर, केंद्र ने राजकोषीय समेकन के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित

की है, साथ ही विकास में सुधार लाने और निजी निवेश में भीड़ के लिए एक अच्छा चक्र बनाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी है। . केंद्र ने एच 1:2023-24 में अपने बजटीय राजस्व का आधे से अधिक हासिल किया, जबकि अपने व्यय को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आधे से भी कम पर सीमित रखा। यह केंद्र के लिए 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के जीएफडी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अच्छा संकेत होगा।

राज्यों ने भी अपने राजकोषीय मापदंडों में मजबूती देखी है, जैसा कि उनके कर राजस्व में निरंतर उछाल से स्पष्ट है। विशेष रूप से, उन्होंने सुधारों से जुड़े केंद्रीय धन और अपने स्वयं के संसाधनों दोनों का उपयोग करके, फ्रंट-लोड कैपेक्स के केंद्र के रुख के अनुरूप अपने पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है। हालाँकि, राज्य अपने पूंजीगत व्यय की गति को व्यय और राजस्व दोनों मोर्चों पर बनाए रखने में कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने और कुछ अन्य राज्यों द्वारा उसी दिशा में आगे बढ़ने की रिपोर्ट से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने वाली विकास करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। जीएसटी मुआवजे की समाप्ति को देखते हुए, व्यय की गुणवत्ता बनाए रखने और समवर्ती रूप से अपनी राजकोषीय क्षमता का विस्तार करते हुए राजकोषीय विवेक के साथ-साथ कर राजस्व में निरंतर उछाल महत्वपूर्ण है। यह राजकोषीय स्थिरता बनाए रखते हुए मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अच्छा संकेत होगा।

परिशिष्ट सारणी

सारणी I: अप्रैल-सितंबर के दौरान केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति

वस्तु	*(₹ हजार करोड़)*				*(प्रतिशत)*			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		साल-दर-साल विकास दर	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**1397.1**	**1169.6**	**2632.3**	**2204.4**	**53.1**	**53.1**	**19.5**	**8.2**
1.1. शुद्ध कर राजस्व	1160.3	1012.0	2330.6	1934.7	49.8	52.3	14.7	9.9
1.2. गैर-कर राजस्व	236.8	157.6	301.7	269.7	78.5	58.4	50.2	-1.7
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	17.3	12.5	24.8	18.0	69.7	69.4	38.7	21.1
2. पूंजीगत प्राप्तियां	**20.2**	**34.2**	**84.0**	**79.3**	**24.0**	**43.1**	**-41.0**	**88.7**
2.1. ऋण की वसूली	13.2	9.6	23.0	14.3	57.5	67.2	37.7	6.6
2.2. अन्य रसीदें	7.0	24.6	61.0	65.0	11.4	37.8	-71.7	169.8
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	**1417.3**	**1203.7**	**2716.3**	**2283.7**	**52.2**	**52.7**	**17.7**	**9.5**
4. राजस्व व्यय	**1628.5**	**1480.7**	**3502.1**	**3194.7**	**46.5**	**46.3**	**10.0**	**6.0**
जिसका कि								
(i) ब्याज भुगतान	484.3	436.7	1080.0	940.7	44.8	46.4	10.9	19.6
5. पूंजीगत व्यय	**490.6**	**342.9**	**1001.0**	**750.2**	**49.0**	**45.7**	**43.1**	**49.5**
जिसका कि								
(i) ऋण और अग्रिम	74.8	23.6	163.8	140.1	45.7	16.8	217.5	20.8
6. कुल व्यय (4+5)	**2119.1**	**1823.6**	**4503.1**	**3944.9**	**47.1**	**46.2**	**16.2**	**12.2**
7. राजस्व घाटा (4-1)	**231.4**	**311.1**	**869.9**	**990.2**	**26.6**	**31.4**	**-25.6**	**-1.4**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**701.9**	**619.8**	**1786.8**	**1661.2**	**39.3**	**37.3**	**13.2**	**17.7**
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4(i)}	**217.5**	**183.2**	**706.8**	**720.5**	**30.8**	**25.4**	**18.8**	**12.3**

स्रोत: लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी II: केंद्र सरकार के वित्त की त्रैमासिक स्थिति

वस्तु	*(₹ हजार करोड़)*				*(प्रतिशत)*					
	ति1		ति2		बीई का प्रतिशत				साल-दर-साल विकास दर	
					ति1		ति2		2023-24	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**588.6**	**568.1**	**808.5**	**601.5**	**22.4**	**25.8**	**30.7**	**27.3**	**3.6**	**34.4**
1.1. शुद्ध कर राजस्व	433.6	505.9	726.7	506.1	18.6	26.1	31.2	26.2	-14.3	43.6
1.2. गैर-कर राजस्व	155.0	62.2	81.8	95.4	51.4	23.1	27.1	35.4	149.3	-14.3
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	9.5	5.1	7.8	7.4	38.5	28.1	31.3	41.3	88.8	4.5
2. पूंजीगत प्राप्तियां	**10.7**	**28.0**	**9.5**	**6.2**	**12.7**	**35.3**	**11.3**	**7.8**	**-61.8**	**52.5**
2.1. ऋण की वसूली	6.5	3.4	6.7	6.2	28.1	24.0	29.3	43.2	89.0	9.3
2.2. अन्य रसीदें	4.2	24.6	2.7	0.0	6.9	37.8	4.5	0.0	-82.8	8658.1
3. कुल प्राप्तियाँ	**599.3**	**596.0**	**818.0**	**607.7**	**22.1**	**26.1**	**30.1**	**26.6**	**0.5**	**34.6**
4. राजस्व व्यय	**772.2**	**772.8**	**856.3**	**707.9**	**22.0**	**24.2**	**24.5**	**22.2**	**-0.1**	**21.0**
जिसका कि										
(i) ब्याज भुगतान	243.7	228.6	240.6	208.1	22.6	24.3	22.3	22.1	6.6	15.6
5. पूंजीगत व्यय	**278.5**	**175.1**	**212.1**	**167.8**	**27.8**	**23.3**	**21.2**	**22.4**	**59.1**	**26.4**
जिसका कि										
(i) ऋण और अग्रिम	44.6	14.1	30.2	9.5	27.2	10.1	18.4	6.8	216.3	219.4
(ii) पूंजीगत परिव्यय	233.9	161.0	181.9	158.4	27.9	26.4	21.7	26.0	45.3	14.9
6. कुल व्यय	**1050.7**	**947.9**	**1068.5**	**875.7**	**23.3**	**24.0**	**23.7**	**22.2**	**10.8**	**22.0**
7. राजस्व घाटा (4-1)	**183.6**	**204.8**	**47.8**	**106.4**	**21.1**	**20.7**	**5.5**	**10.7**	**-10.4**	**-55.1**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**451.4**	**351.9**	**250.5**	**268.0**	**25.3**	**21.2**	**14.0**	**16.1**	**28.3**	**-6.5**
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4(i)}	**207.7**	**123.3**	**9.9**	**59.9**	**29.4**	**17.1**	**1.4**	**8.3**	**68.5**	**-83.5**

स्रोत: लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी III: अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति								
वस्तु	*(₹ हजार करोड़)*				*(प्रतिशत)*			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		साल-दर-साल विकास दर	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,499.9**	**1,625.0**	**3,627.6**	**4,064.2**	**41.3**	**40.0**	**26.2**	**8.3**
1.1. राजस्व का टैक्स	1,141.9	1,308.7	2,514.4	3,025.2	45.4	43.3	32.4	14.6
1.2. गैर-कर राजस्व	112.5	134.5	305.8	332.3	36.8	40.5	33.5	19.6
1.3. सहायता अनुदान और योगदान	245.5	181.9	807.5	706.7	30.4	25.7	1.4	-25.9
2. पूंजीगत प्राप्तियां	**3.5**	**4.0**	**19.8**	**42.8**	**17.7**	**9.4**	**-25.0**	**15.4**
2.1. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	3.4	3.7	13.8	18.9	24.7	19.4	-25.3	8.2
2.2. अन्य रसीदें	0.1	0.4	6.0	23.9	1.5	1.5	-7.8	285.0
3. कुल प्राप्तियाँ	**1,503.4**	**1,629.0**	**3,647.4**	**4,107.0**	**41.2**	**39.7**	**26.0**	**8.4**
4. राजस्व व्यय	**1,558.0**	**1,697.4**	**3,753.9**	**4,137.0**	**41.5**	**41.0**	**16.3**	**8.9**
4.1 ब्याज भुगतान	188.9	211.2	455.6	501.8	41.5	42.1	20.6	11.8
5. पूंजीगत व्यय	**201.0**	**296.1**	**742.8**	**885.4**	**27.1**	**33.4**	**7.5**	**47.3**
5.1 पूंजीगत परिव्यय	177.4	270.7	683.1	801.9	26.0	33.8	2.9	52.6
6. कुल व्यय	**1,758.9**	**1,993.5**	**4,496.6**	**5,022.4**	**39.1**	**39.7**	**15.2**	**13.3**
7. राजस्व घाटा (4-1)	**58.1**	**72.4**	**126.2**	**72.8**	**46.0**	**99.4**	**-61.5**	**24.6**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**255.6**	**364.4**	**849.2**	**915.4**	**30.1**	**39.8**	**-23.3**	**42.6**
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	**66.6**	**153.2**	**393.6**	**413.6**	**16.9**	**37.0**	**-62.3**	**129.9**

नोट: डेटा 25 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; और राज्यों के बजट दस्तावेज़।

सारणी IV: राज्य सरकार के वित्त की त्रैमासिक स्थिति										
वस्तु	*(₹ हजार करोड़)*				*(प्रतिशत)*					
	वास्तविक				बीई का प्रतिशत				साल-दर-साल विकास दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2023-24	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	ति1	ति2
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**715.8**	**825.2**	**784.1**	**799.8**	**19.7**	**20.3**	**21.6**	**19.7**	**15.3**	**2.0**
1.1. राजस्व का टैक्स	523.2	640.2	618.7	668.5	20.8	21.2	24.6	22.1	22.4	8.1
1.2. गैर-कर राजस्व	59.8	53.9	52.7	80.6	19.5	16.2	17.2	24.3	-9.9	52.9
1.3. सहायता अनुदान और योगदान	132.8	131.1	112.7	50.8	16.4	18.6	14.0	7.2	-1.3	-55.0
2. पूंजीगत प्राप्तियां	**2.1**	**1.8**	**1.4**	**2.2**	**10.4**	**4.2**	**7.3**	**5.2**	**-12.0**	**54.8**
2.1. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	2.0	1.7	1.4	1.9	14.8	9.2	9.9	10.2	-14.2	41.6
2.2. अन्य रसीदें	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	208.1	306.6
3. कुल प्राप्तियाँ	**717.9**	**827.0**	**785.5**	**802.0**	**19.7**	**20.1**	**21.5**	**19.5**	**15.2**	**2.1**
4. राजस्व व्यय	**728.7**	**785.4**	**829.2**	**912.0**	**19.4**	**19.0**	**22.1**	**22.0**	**7.8**	**10.0**
4.1 ब्याज भुगतान	83.0	87.9	105.9	123.4	18.2	17.5	23.3	24.6	5.9	16.4
5. पूंजीगत व्यय	**71.1**	**122.6**	**129.9**	**173.5**	**9.6**	**13.8**	**17.5**	**19.6**	**72.4**	**33.6**
5.1. पूँजी परिव्यय	62.6	108.1	114.8	162.5	9.2	13.5	16.8	20.3	72.9	41.5
6. कुल व्यय	**799.8**	**907.9**	**959.1**	**1,085.5**	**17.8**	**18.1**	**21.3**	**21.6**	**13.5**	**13.2**
7. राजस्व घाटा	**12.9**	**-39.8**	**45.2**	**112.2**	**10.2**	**-54.7**	**35.8**	**154.0**	**-408.3**	**148.4**
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	**82.0**	**80.9**	**173.6**	**283.5**	**9.7**	**8.8**	**20.4**	**31.0**	**-1.3**	**63.3**
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	**-1.0**	**-6.9**	**67.7**	**160.1**	**-0.3**	**-1.7**	**17.2**	**38.7**	**588.8**	**136.7**

नोट: डेटा 25 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; और राज्यों के बजट दस्तावेज़।